

R-1792-I/16

श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

द्वारा आज दि 6/6/16 को

प्रस्तुत

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

~~शेलेन्द्र सिंह डायरेक्टर एस.एस.क्यू.इनफ्राटेक प्रा.लि.~~
निवासी छतरपुर जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 22/बी-121/15-16 पारित आदेश दिनांक 03/05/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा क्र 575/1 रकवा 0.332 में से 0.104, खसरा क्र 592/1 रकवा 0.769 में 0.492, खसरा क्र 592/2 रकवा 0.466 में से 0.294, 591 रकवा 0.955 में से 0.621 एवं 590 रकवा 0.700 में से 0.438 कुल किता 5 कुल रकवा 1.949 हे भूमि के विकास हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 3/5/16 को अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/3/16 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का


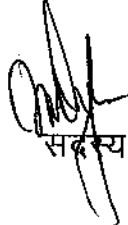
(निवेन्द्र सिंह)
एस.एस.क्यू.
(94251-71223)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1792-7/16 जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	<p>1- आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने।</p> <p>2- मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 22/बी-121/वर्ष 15-16 में पारित आदेश दिनांक 03/5/16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि मौजा बगौता स्थित खसरा नंबर 575/1, 592/1, 592/2, 591, 590 कुल रकवा 1.949 हे भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जो वर्तमान में आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के विकास हेतु अनुमति प्रदाय किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 11/4/16 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा दिनांक 13/4/16 को प्रस्तुत किए जाने उपरांत अपर कलेक्टर द्वारा समस्त जांच हो जाने के पश्चात् भी दिनांक 3/5/16 को पुनः जांच किए जाने का आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक की समस्त बिन्दुओं की जांच एक बार पूर्ण होने के उपरांत भी अपर कलेक्टर द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं जिससे स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर प्रकरण में कोई आदेश पारित ना कर अनावश्यक रूप से प्रकरण को विचाराधीन रखकर आवेदक को क्षति पहुंचा रहे हैं। उक्त आधार पर आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकास की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए यह निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>4- आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की भूमिस्वामी हक की भूमि है तथा उसके द्वारा भूमि के विकास हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा दिनांक 2-3-16 को भूमि का व्यपवर्तन किया गया है तथा ग्राम पंचायत बगौता, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड छतरपुर, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनापत्ति एवं अनुमोदन किया गया है एवं नगर पालिका छतरपुर द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित किया जा चुका है। प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11/4/16 को अनुविभागीय अधिकारी से चाहा गया जांच प्रतिवेदन भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13/4/16 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त कलेक्टर छतरपुर को आदेशित किया जाता है कि आवेदक को निर्धारित प्रारूप में विकास की अनुमति प्रदाय करें। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>  <p style="text-align: center;">सदस्य</p>	